

भारत में स्कूली विद्यार्थियों के अधिगम परिणाम: प्रवृत्तियाँ, प्रगति और चुनौतियाँ

श्वेता

शिक्षक, बेसिक शिक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश, भारत

सारांश

भारत में विद्यालयी शिक्षा ने पिछले दो दशकों में पहुँच, नामांकन, विद्यालयों की संख्या, आधारभूत सुविधाओं, छात्रवृत्तियों, बालिका शिक्षा, वंचित समुदायों की भागीदारी और शैक्षिक योजनाओं के विस्तार के स्तर पर उल्लेखनीय प्रगति की है, किन्तु विद्यालयी व्यवस्था की वास्तविक सफलता का आकलन केवल इस आधार पर नहीं किया जा सकता कि कितने बच्चे विद्यालय में नामांकित हैं या कितने वर्ष तक विद्यालय में बने रहते हैं। शिक्षा की गुणवत्ता का सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न यह है कि विद्यार्थी विद्यालय में बिताए गए समय के दौरान वास्तव में कितना पढ़ना, समझना, लिखना, गणना करना, तर्क करना, समस्या का समाधान करना और अर्जित ज्ञान को जीवन की परिस्थितियों में लागू करना सीखते हैं। प्रस्तुत अध्ययन का उद्देश्य भारत में स्कूली विद्यार्थियों के अधिगम परिणामों की प्रमुख प्रवृत्तियों, हाल की प्रगति, कक्षा-स्तरीय परिवर्तन, सामाजिक एवं क्षेत्रीय असमानताओं और उन संरचनात्मक चुनौतियों का विश्लेषण करना है जो गुणवत्तापूर्ण अधिगम को प्रभावित करती हैं। अध्ययन पूर्णतः द्वितीयक आँकड़ों पर आधारित है और इसमें वार्षिक शिक्षा स्थिति सर्वेक्षण, राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वेक्षण, परख राष्ट्रीय सर्वेक्षण तथा विद्यालयी शिक्षा से संबंधित सरकारी प्रशासनिक आँकड़ों का उपयोग किया गया है। उपलब्ध साक्ष्यों से पता चलता है कि महामारी के बाद प्रारम्भिक कक्षाओं में पढ़ने और अंकगणित की बुनियादी क्षमताओं में स्पष्ट सुधार हुआ है तथा वर्ष २०२२ से २०२४ के बीच सरकारी विद्यालयों के विद्यार्थियों में यह सुधार विशेष रूप से उल्लेखनीय रहा है। इसके विपरीत, उच्चतर कक्षाओं में गणित, विज्ञान, अवधारणात्मक समझ और जटिल समस्या समाधान से संबंधित उपलब्धियाँ अपेक्षाकृत कमजोर बनी हुई हैं। अध्ययन यह भी दर्शाता है कि राष्ट्रीय औसत के भीतर राज्यों, सामाजिक समूहों, विद्यालयी परिस्थितियों, भाषा, घरेलू संसाधनों और माध्यमिक स्तर तक विद्यालय में बने रहने की क्षमता के आधार पर महत्वपूर्ण अंतर उपस्थित हैं। निष्कर्षतः भारत में विद्यालयी शिक्षा को केवल नामांकन और आधारभूत संरचना केन्द्रित दृष्टिकोण से आगे बढ़ाकर वास्तविक कक्षा-अधिगम, आधारभूत साक्षरता एवं संख्याज्ञान, शिक्षक सहायता, स्तरानुकूल शिक्षण, सतत मूल्यांकन, स्थानीय भाषा और सामाजिक संदर्भ के अनुरूप शैक्षिक हस्तक्षेपों पर अधिक केन्द्रित करने की आवश्यकता है।

ARTICLE INFORMATION

Article Title	भारत में स्कूली विद्यार्थियों के अधिगम परिणाम: प्रवृत्तियाँ, प्रगति और चुनौतियाँ
Article Type	Research Article
Volume / Issue	Volume 1 Issue 1
Issue Period	January - March 2026
Licence	CC BY 4.0
Corresponding Author	Shweta
Email	
Authors	Shweta
Affiliations	Teacher, basic education department, u.p. india
Peer Review	Double Blind Peer Review

मुख्य शब्द: अधिगम परिणाम, विद्यालयी शिक्षा, आधारभूत साक्षरता, संख्याज्ञान, विद्यार्थी उपलब्धि, शैक्षिक असमानता, भारत

१. प्रस्तावना

विद्यालयी शिक्षा किसी भी समाज के मानवीय, सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक विकास की आधारशिला है। विद्यालय केवल ज्ञान के प्रसारण का संस्थान नहीं, बल्कि ऐसा सामाजिक परिवेश है जहाँ बालक भाषा, संख्या, तर्क, अनुशासन, सहयोग, आत्मविश्वास, नागरिकता, समस्या समाधान और जीवन के विविध अनुभवों को व्यवस्थित रूप से सीखता है। इसलिए विद्यालयी शिक्षा की गुणवत्ता का प्रश्न केवल पाठ्यक्रम पूरा करने या वार्षिक परीक्षा में अंक प्राप्त करने तक सीमित नहीं रह सकता। अधिगम परिणाम इस व्यापक प्रश्न का उत्तर देने का प्रयास करते हैं कि विद्यार्थी किसी निश्चित कक्षा या आयु तक वास्तव में क्या जानता है, क्या समझता है और क्या कर पाने में सक्षम है। यदि कोई विद्यार्थी वर्षों तक विद्यालय में उपस्थित रहता है लेकिन अपनी कक्षा के अनुरूप पाठ को समझकर पढ़ नहीं पाता, सामान्य गणितीय क्रियाएँ नहीं कर पाता या अर्जित ज्ञान का सरल परिस्थितियों में प्रयोग नहीं कर पाता, तो नामांकन की उपलब्धि अधूरी रह जाती है। इसी कारण वर्तमान शैक्षिक विमर्श में विद्यालय तक पहुँच से आगे बढ़कर विद्यालय में होने वाले वास्तविक अधिगम पर अधिक ध्यान दिया जा रहा है। भारत में सर्वशिक्षा के विस्तार, निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा, मध्याह्न भोजन, छात्रवृत्तियों, पाठ्यपुस्तक सहायता, बालिका शिक्षा और सामाजिक रूप से वंचित वर्गों के लिए विभिन्न योजनाओं ने विद्यालयी भागीदारी को व्यापक बनाया है, फिर भी अधिगम की गुणवत्ता समान गति से नहीं बढ़ी। इस विरोधाभास ने नीति-निर्माताओं, शिक्षकों और शोधकर्ताओं के सामने यह प्रश्न रखा है कि विद्यालयी व्यवस्था में प्रवेश और बने रहने को वास्तविक ज्ञान और कौशल में किस प्रकार परिवर्तित किया जाए।

भारत की विद्यालयी व्यवस्था विश्व की सबसे बड़ी शिक्षा व्यवस्थाओं में से एक है और इसकी विविधता भी अत्यंत व्यापक है। वर्ष २०२४-२५ के सरकारी विद्यालयी आँकड़ों के अनुसार देश में लगभग २४.६९ करोड़ विद्यार्थी विद्यालयी शिक्षा में नामांकित थे तथा लगभग १.०९ करोड़ शिक्षक इस व्यवस्था से जुड़े थे। विद्यालयों की कुल संख्या लगभग १४.७१ लाख थी, जिनमें सरकारी, सरकारी सहायता प्राप्त, निजी और अन्य प्रकार के विद्यालय सम्मिलित थे। यह विशाल आकार अपने आप में प्रशासनिक उपलब्धि है, किन्तु इसी के साथ यह चुनौती भी उत्पन्न करता है कि विभिन्न राज्यों, जिलों, भाषाओं, सामाजिक समूहों और विद्यालयी व्यवस्थाओं में सीखने की गुणवत्ता को किस प्रकार तुलनीय और न्यायसंगत बनाया जाए। राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वेक्षण २०२१ ने यह महत्वपूर्ण तथ्य सामने रखा कि कक्षा बढ़ने के साथ औसत उपलब्धि में गिरावट दिखाई दी। कक्षा ३ का समग्र औसत लगभग ५९ प्रतिशत, कक्षा ५ का लगभग ४९ प्रतिशत, कक्षा ८ का लगभग ४५ प्रतिशत और कक्षा १० का लगभग ३८ प्रतिशत था। इस प्रवृत्ति से यह संकेत मिलता है कि प्रारम्भिक कक्षाओं में बनी छोटी अधिगम-कमियाँ समय के साथ समाप्त होने के बजाय अनेक विद्यार्थियों के लिए बढ़ सकती हैं। दूसरी ओर वर्ष २०२४ के ग्रामीण भारत संबंधी अध्ययन ने प्रारम्भिक पढ़ने और अंकगणित में महामारी के बाद उल्लेखनीय सुधार दर्ज किया, विशेष रूप से सरकारी विद्यालयों में। यह मिश्रित परिदृश्य बताता है कि भारतीय विद्यालयी शिक्षा में एक ओर पुनरुद्धार और प्रगति के स्पष्ट संकेत हैं, तो दूसरी ओर उच्चतर कक्षाओं में अवधारणात्मक अधिगम और गहरी समझ से जुड़ी चुनौतियाँ बनी हुई हैं।

२. अधिगम परिणाम की अवधारणा और महत्त्व

अधिगम परिणाम से आशय उन प्रत्यक्ष ज्ञानात्मक, भाषिक, गणितीय, व्यावहारिक और अनुप्रयोगात्मक क्षमताओं से है जिन्हें विद्यार्थी किसी निश्चित शिक्षण-अवधि के बाद प्रदर्शित कर सके। प्रारम्भिक स्तर पर इनमें अक्षर और शब्द पहचानना, सरल वाक्य पढ़ना, पढ़े गए पाठ का अर्थ समझना, संख्याएँ पहचानना, जोड़-घटाव करना और सामान्य दैनिक समस्याओं को गणितीय रूप में हल करना सम्मिलित हो सकता है। उच्च प्राथमिक और माध्यमिक स्तर पर अधिगम परिणाम अधिक जटिल हो जाते हैं और उनसे अपेक्षा की जाती है कि विद्यार्थी

अवधारणाओं के बीच संबंध समझे, प्रमाण के आधार पर निष्कर्ष निकाले, तर्क करे, विभिन्न स्रोतों से जानकारी का विश्लेषण करे, वैज्ञानिक कारण-परिणाम संबंधों को समझे और सामाजिक तथा वास्तविक जीवन की समस्याओं पर अर्जित ज्ञान लागू करे। इस प्रकार अधिगम परिणाम को परीक्षा-अंक का पर्याय नहीं माना जा सकता। परीक्षा अंक किसी विद्यार्थी की शैक्षिक उपलब्धि का एक संकेत अवश्य हैं, परन्तु वास्तविक अधिगम का अर्थ स्मरण, समझ, प्रयोग, विश्लेषण, तर्क और ज्ञान-स्थानांतरण की संयुक्त क्षमता है। यही कारण है कि हाल के राष्ट्रीय सर्वेक्षण केवल प्रश्न-पत्र आधारित अंक देने के बजाय दक्षता, समझ और अनुप्रयोग के स्तर को मापने का प्रयास करते हैं।

अधिगम परिणाम का महत्व इस तथ्य में निहित है कि यह शिक्षा की गुणवत्ता को अधिक प्रत्यक्ष रूप से सामने लाता है। नामांकन बढ़ने से यह पता चलता है कि बच्चे शिक्षा व्यवस्था तक पहुँचे हैं, परन्तु अधिगम परिणाम यह बताते हैं कि उस पहुँच का वास्तविक शैक्षिक लाभ क्या हुआ। यदि किसी विद्यालय में उपस्थिति अच्छी है, आधारभूत सुविधाएँ पर्याप्त हैं और पाठ्यपुस्तकें समय पर उपलब्ध हैं, फिर भी विद्यार्थियों की पढ़ने या गणना करने की क्षमता कमजोर है, तो यह संकेत है कि शिक्षण की प्रक्रिया, कक्षा प्रबंधन, मूल्यांकन, भाषा, पाठ्यक्रम की गति या विद्यार्थी सहायता में समस्या हो सकती है। दूसरी ओर सीमित संसाधनों वाले कुछ विद्यालय यदि बेहतर अधिगम परिणाम प्रदर्शित करते हैं तो इससे स्पष्ट होता है कि शिक्षक की भूमिका, नेतृत्व, विद्यालय संस्कृति, नियमित अभ्यास और समुदाय का सहयोग भी उतने ही महत्वपूर्ण हैं। इस दृष्टि से अधिगम परिणाम केवल विद्यार्थियों का मापन नहीं, बल्कि पूरी विद्यालयी व्यवस्था की कार्यक्षमता का संकेतक हैं।

३. अध्ययन की आवश्यकता

भारत में विद्यालयी शिक्षा के संबंध में लंबे समय तक मुख्य चिंता विद्यालयों की उपलब्धता, नामांकन और निरंतरता रही। यह चिंता ऐतिहासिक रूप से उचित थी क्योंकि बड़ी संख्या में बच्चे विद्यालय से बाहर थे और विशेष रूप से बालिकाओं, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, ग्रामीण और आर्थिक रूप से कमजोर समुदायों की पहुँच सीमित थी। पिछले वर्षों में इस क्षेत्र में पर्याप्त विस्तार हुआ है, किन्तु जैसे-जैसे पहुँच का दायरा बढ़ा, शिक्षा की गुणवत्ता और अधिगम का प्रश्न अधिक प्रमुख होता गया। विद्यालय में प्रवेश प्राप्त कर लेने के बाद यदि विद्यार्थी अपनी कक्षा के अनुरूप बुनियादी कौशल विकसित नहीं कर पाता, तो आगे की प्रत्येक कक्षा उसके लिए कठिन होती जाती है। प्रारम्भिक पढ़ने में कमजोरी विज्ञान, सामाजिक विज्ञान और गणित सहित लगभग सभी विषयों की समझ को प्रभावित करती है, जबकि आधारभूत संख्याज्ञान की कमी उच्चतर गणित और दैनिक जीवन की आर्थिक तथा तार्किक समस्याओं को समझने में बाधा उत्पन्न करती है। इसी कारण विद्यालयी शिक्षा की प्रगति का विश्लेषण अब प्रवेश और नामांकन के साथ अधिगम की वास्तविक गुणवत्ता को भी समाहित करता है। प्रस्तुत अध्ययन की आवश्यकता इसी संदर्भ में है कि विभिन्न राष्ट्रीय स्रोतों से उपलब्ध नवीन साक्ष्यों को एक साथ देखकर यह समझा जाए कि भारत में अधिगम कहाँ सुधरा है, कहाँ ठहरा है और किन स्तरों पर नई चुनौतियाँ उभर रही हैं।

४. संबंधित साहित्य का विवेचन

भारत में विद्यालयी अधिगम पर उपलब्ध राष्ट्रीय स्तर के अध्ययन कई पूरक दृष्टिकोण प्रस्तुत करते हैं। राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वेक्षण २०२१ ने कक्षा ३, ५, ८ और १० के विद्यार्थियों का व्यापक स्तर पर आकलन किया और भाषा, गणित, पर्यावरण अध्ययन, विज्ञान तथा सामाजिक विज्ञान जैसे विषयों में उनकी उपलब्धि की स्थिति प्रस्तुत की। इस सर्वेक्षण की प्रमुख विशेषता यह थी कि इसने विद्यालय-आधारित संगठित नमूने के माध्यम से विभिन्न कक्षाओं की दक्षता का तुलनात्मक चित्र दिया। प्राप्त निष्कर्षों में कक्षा बढ़ने के साथ औसत उपलब्धि में क्रमशः कमी दिखाई दी, जिससे यह प्रश्न उभरा कि क्या प्रारम्भिक वर्षों में उत्पन्न अधिगम-अंतर बाद की कक्षाओं में संचयित होता जा रहा है। इसी संदर्भ में वार्षिक शिक्षा स्थिति सर्वेक्षण विशेष महत्व रखता है क्योंकि यह मुख्यतः ग्रामीण परिवारों में जाकर बच्चों की पढ़ने और अंकगणित की वास्तविक क्षमता का प्रत्यक्ष परीक्षण करता है।

वर्ष २०२४ के सर्वेक्षण ने महामारी के बाद अधिगम में सुधार की मजबूत तस्वीर प्रस्तुत की। सरकारी विद्यालयों में कक्षा ३ के वे विद्यार्थी जो कम से कम कक्षा २ स्तर का पाठ पढ़ सकते थे, वर्ष २०१८ में २०.९ प्रतिशत थे; यह अनुपात वर्ष २०२२ में घटकर १६.३ प्रतिशत हो गया, परन्तु वर्ष २०२४ में बढ़कर २३.४ प्रतिशत हो गया। कक्षा ५ के सरकारी विद्यालयों में कक्षा २ स्तर का पाठ पढ़ पाने वाले विद्यार्थियों का अनुपात वर्ष २०१८ के ४४.२ प्रतिशत से घटकर वर्ष २०२२ में ३८.५ प्रतिशत हुआ और वर्ष २०२४ में पुनः बढ़कर ४४.८ प्रतिशत पहुँच गया। ये आँकड़े बताते हैं कि महामारी के दौरान हुई शैक्षिक क्षति के बाद अनेक क्षेत्रों में पुनरुद्धार हुआ और कुछ संकेतकों पर स्थिति महामारी-पूर्व स्तर से भी आगे गई।

अंकगणित संबंधी निष्कर्ष भी इसी दिशा की पुष्टि करते हैं। कक्षा ३ के वे विद्यार्थी जो कम से कम घटाव का प्रश्न हल कर सकते थे, अखिल भारतीय स्तर पर वर्ष २०१८ में २८.२ प्रतिशत, वर्ष २०२२ में २५.९ प्रतिशत और वर्ष २०२४ में ३३.७ प्रतिशत थे। सरकारी विद्यालयों में यह अनुपात क्रमशः २०.९ प्रतिशत, २०.२ प्रतिशत और २७.६ प्रतिशत रहा। कक्षा ५ के विद्यार्थियों में भाग का प्रश्न हल करने की क्षमता वर्ष २०१८ के २७.९ प्रतिशत से घटकर वर्ष २०२२ में २५.६ प्रतिशत हुई और वर्ष २०२४ में बढ़कर ३०.७ प्रतिशत हो गई। इन आँकड़ों से यह स्पष्ट है कि प्रारम्भिक गणितीय दक्षताओं में सुधार हुआ है, किन्तु यह सुधार अभी सार्वभौमिक दक्षता में परिवर्तित नहीं हुआ है। यदि कक्षा ५ में भी बड़ी संख्या में विद्यार्थी साधारण भाग का प्रश्न हल नहीं कर पाते, तो आगे के गणितीय पाठ्यक्रम में उनके सामने कठिनाई स्वाभाविक है। इसलिए साहित्य यह संकेत करता है कि आधारभूत स्तर पर प्रगति को बनाए रखते हुए गुणवत्ता का अगला चरण अवधारणात्मक समझ, नियमित अभ्यास और कठिनाई की शीघ्र पहचान होना चाहिए।

परख राष्ट्रीय सर्वेक्षण २०२४ ने इस चर्चा को आगे बढ़ाते हुए कक्षा ३, ६ और ९ के विद्यार्थियों के व्यापक आकलन का आधार प्रदान किया। कक्षा ६ में भाषा का राष्ट्रीय औसत लगभग ५७ प्रतिशत, गणित का लगभग ४६ प्रतिशत और आसपास के संसार से संबंधित विषय का लगभग ४९ प्रतिशत रहा। कक्षा ९ में भाषा का औसत लगभग ५४ प्रतिशत, गणित का ३७ प्रतिशत, विज्ञान का ४० प्रतिशत और सामाजिक विज्ञान का ४० प्रतिशत रहा। इससे यह संकेत मिलता है कि प्रारम्भिक पढ़ने और सरल गणना की क्षमताओं में सुधार होने के बावजूद उच्चतर कक्षाओं में गणितीय तर्क, वैज्ञानिक अवधारणाओं और विषयगत गहराई के स्तर पर महत्वपूर्ण चुनौतियाँ बनी हुई हैं। इसी सर्वेक्षण में प्रारम्भिक स्तर पर लिंग के आधार पर अंतर बहुत सीमित था; कक्षा ३ में छात्राओं का भाषा में औसत प्रदर्शन छात्रों से थोड़ा अधिक था, जबकि गणित में दोनों का प्रदर्शन लगभग समान था। ग्रामीण और नगरीय विद्यार्थियों के बीच भी अंतर अपेक्षाकृत छोटा पाया गया। यह तथ्य इस सामान्य धारणा को चुनौती देता है कि प्रत्येक परिस्थिति में निजी या नगरीय विद्यालय स्वतः उच्चतर अधिगम सुनिश्चित करते हैं। इससे विद्यालयी नेतृत्व, शिक्षक सहयोग, नियमितता, स्थानीय संदर्भ और कक्षा प्रक्रियाओं की भूमिका अधिक स्पष्ट होती है।

५. अध्ययन के उद्देश्य और शोध प्रश्न

प्रस्तुत अध्ययन का प्रथम उद्देश्य भारत में स्कूली विद्यार्थियों के अधिगम परिणामों की हाल की प्रवृत्तियों का विश्लेषण करना है ताकि यह समझा जा सके कि महामारी-पूर्व, महामारी-पश्चात और नवीनतम अवधि में पढ़ने तथा गणना की क्षमताओं में क्या परिवर्तन हुआ। दूसरा उद्देश्य प्रारम्भिक कक्षाओं में आधारभूत साक्षरता और संख्याज्ञान की प्रगति तथा उच्चतर कक्षाओं में गणित, विज्ञान और भाषा संबंधी उपलब्धियों के बीच संबंध को समझना है। तीसरा उद्देश्य लिंग, सामाजिक समूह, ग्रामीण-नगरीय स्थिति और विद्यालय प्रबंधन के आधार पर अधिगम में दिखाई देने वाले अंतर का विवेचन करना है। चौथा उद्देश्य विद्यालयी आधारभूत सुविधाओं, शिक्षक उपलब्धता, माध्यमिक स्तर तक निरंतरता और स्थानीय परिस्थितियों के संदर्भ में उन चुनौतियों की पहचान करना है जो अधिगम परिणामों में स्थायी सुधार को प्रभावित करती हैं। इन्हीं उद्देश्यों के अनुरूप अध्ययन यह जानने का प्रयास करता है कि हाल के वर्षों में अधिगम की दिशा क्या रही है, कौन-से क्षेत्र उल्लेखनीय रूप से

सुधरे हैं, किन विषयों और कक्षाओं में कमजोरी अधिक है, और भविष्य में नीति तथा विद्यालय स्तर पर किस प्रकार के हस्तक्षेप अधिक प्रभावी हो सकते हैं।

६. शोध पद्धति

यह अध्ययन वर्णनात्मक और विश्लेषणात्मक प्रकृति का है तथा पूर्णतः द्वितीयक आँकड़ों पर आधारित है। किसी नए क्षेत्रीय सर्वेक्षण, साक्षात्कार या प्रश्नावली का प्रयोग नहीं किया गया है। अध्ययन में चार प्रकार के स्रोतों को प्रमुखता दी गई है: विद्यालयी प्रशासनिक आँकड़े, ग्रामीण परिवारों में बच्चों की पढ़ने और अंकगणित की प्रत्यक्ष जाँच, राष्ट्रीय स्तर के विद्यालय-आधारित उपलब्धि सर्वेक्षण और सरकारी शैक्षिक नीति तथा सांख्यिकीय प्रतिवेदन। समयगत प्रवृत्तियों के लिए उन सूचकों को प्राथमिकता दी गई है जिन्हें एक ही सर्वेक्षण में समान पद्धति से अलग-अलग वर्षों में मापा गया है। विभिन्न सर्वेक्षणों के प्रतिशतों को प्रत्यक्ष रूप से एक-दूसरे के बराबर नहीं माना गया क्योंकि उनके नमूने, परीक्षण उपकरण, कक्षा-समूह और मूल्यांकन पद्धतियाँ अलग हैं। विश्लेषण में प्रतिशत परिवर्तन, कक्षा-स्तरीय अंतर, विषयगत प्रदर्शन, सामाजिक समूहों की तुलना और विद्यालयी व्यवस्था के व्यापक संकेतकों का वर्णनात्मक विवेचन किया गया है। इस पद्धति की शक्ति यह है कि यह किसी एक परीक्षा के परिणाम पर निर्भर रहने के बजाय अनेक आधिकारिक और व्यापक स्रोतों को एक समेकित व्याख्या में जोड़ती है, परन्तु इसकी सीमा यह है कि द्वितीयक आँकड़े कारणात्मक संबंधों को प्रत्यक्ष रूप से सिद्ध नहीं कर सकते।

७. भारत में विद्यालयी शिक्षा का विस्तार और अधिगम का प्रश्न

भारत की विद्यालयी व्यवस्था में नामांकन और विद्यालयी पहुँच का विस्तार अत्यंत महत्वपूर्ण उपलब्धि है। वर्ष २०२४-२५ में लगभग २४.६९ करोड़ विद्यार्थियों का विद्यालयों में नामांकन दर्ज किया गया, जिनमें लगभग ११.९३ करोड़ छात्राएँ और १२.७६ करोड़ छात्र थे। शिक्षकों की संख्या लगभग १.०१ करोड़ रही। लगभग १४.७१ लाख विद्यालयों का व्यापक जाल देश के विभिन्न ग्रामीण, नगरीय, पर्वतीय, जनजातीय और सीमावर्ती क्षेत्रों तक फैला हुआ है। इन आँकड़ों से स्पष्ट है कि विद्यालयी व्यवस्था ने भौगोलिक पहुँच के स्तर पर एक व्यापक ढाँचा तैयार कर लिया है, परन्तु इसी के भीतर गुणवत्ता की समस्या अधिक स्पष्ट होकर सामने आती है। यदि विद्यार्थियों को विद्यालय में प्रवेश मिल जाता है लेकिन वे आधारभूत पढ़ने और गणना की क्षमता के बिना उच्च कक्षाओं में पहुँचते हैं, तो विद्यालयी प्रगति केवल प्रशासनिक रूप से दिखाई देती है, शैक्षिक रूप से नहीं। इसी कारण वर्तमान नीति-विमर्श में नामांकन के साथ वास्तविक अधिगम को भी समान महत्व दिया जा रहा है। माध्यमिक स्तर पर यह चुनौती और गहरी हो जाती है। वर्ष २०२४-२५ में माध्यमिक स्तर का सकल नामांकन अनुपात लगभग ६८.५ प्रतिशत था और विद्यालय त्याग दर प्राथमिक स्तर की तुलना में माध्यमिक स्तर पर स्पष्ट रूप से अधिक थी। यह परिस्थिति बताती है कि विद्यालयी शिक्षा में गुणवत्ता, निरंतरता और उपलब्धि को अलग-अलग नहीं बल्कि परस्पर जुड़े हुए प्रश्नों के रूप में देखना चाहिए। कमजोर अधिगम विद्यार्थी को पाठ्यक्रम से दूर करता है, पाठ्यक्रम से दूरी उपस्थिति और रुचि को कम कर सकती है, और अंततः विद्यालय छोड़ने का जोखिम बढ़ सकता है।

८. प्रारम्भिक पढ़ने की क्षमता: गिरावट से पुनरुद्धार तक

प्रारम्भिक पढ़ने की क्षमता विद्यालयी अधिगम की सबसे बुनियादी शर्त है क्योंकि पढ़ना केवल भाषा-विषय की दक्षता नहीं, बल्कि आगे के लगभग सभी विषयों के अध्ययन का माध्यम है। यदि विद्यार्थी पाठ को सहजता से नहीं पढ़ पाता या पढ़कर अर्थ नहीं समझ पाता, तो विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, गणितीय प्रश्नों और निर्देशों को समझना भी कठिन हो जाता है। ग्रामीण भारत से प्राप्त समयगत आँकड़े इस क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण परिवर्तन दर्शाते हैं। सरकारी विद्यालयों में कक्षा ३ के वे विद्यार्थी जो कम से कम कक्षा २ स्तर का पाठ पढ़ सकते थे, वर्ष २०१८ में २०.९ प्रतिशत थे। महामारी और विद्यालय बंद रहने की अवधि के बाद वर्ष २०२२ में यह अनुपात

घटकर १६.३ प्रतिशत रह गया, जो अधिगम हानि की गंभीरता को दर्शाता है। लेकिन वर्ष २०२४ में यह बढ़कर २३.४ प्रतिशत पहुँच गया। यह सुधार दो कारणों से महत्वपूर्ण है: पहला, इसने महामारी के दौरान हुई गिरावट की भरपाई की; दूसरा, यह वर्ष २०१८ के स्तर से भी आगे निकल गया। कक्षा ५ के सरकारी विद्यालयों में भी यही प्रवृत्ति दिखाई दी, जहाँ कक्षा २ स्तर का पाठ पढ़ पाने वाले विद्यार्थियों का अनुपात २०१८ के ४४.२ प्रतिशत से २०२२ में ३८.५ प्रतिशत तक गिरा और २०२४ में ४४.८ प्रतिशत तक लौट आया। इन परिणामों से यह संकेत मिलता है कि आधारभूत साक्षरता पर लक्षित प्रयास, विद्यालयों का नियमित खुलना, शिक्षक का पुनः सक्रिय संपर्क, घर और समुदाय में बढ़ी शैक्षिक जागरूकता तथा विशेष अभ्यास कार्यक्रमों ने सुधार में भूमिका निभाई हो सकती है। फिर भी यह तथ्य उतना ही महत्वपूर्ण है कि कक्षा ३ के अधिकांश विद्यार्थी अभी भी कक्षा २ स्तर का पाठ सहजता से नहीं पढ़ पाते थे। इसलिए उपलब्धि को संतोष का कारण मानने के बजाय आगे की रणनीति का आधार बनाना अधिक उचित होगा।

९. अंकगणितीय क्षमता की प्रवृत्तियाँ

अंकगणित की आधारभूत समझ भविष्य के गणितीय अधिगम की नींव है और इसका महत्व विद्यालय से बाहर के दैनिक जीवन में भी बना रहता है। संख्या-बोध, जोड़, घटाव, गुणा, भाग, अनुपात और साधारण गणना जैसी क्षमताएँ आर्थिक व्यवहार, समय, मापन, वस्तुओं की तुलना और तार्किक सोच से जुड़ी हैं। उपलब्ध आँकड़े यह बताते हैं कि महामारी के बाद अंकगणितीय अधिगम में भी सुधार हुआ। कक्षा ३ के वे विद्यार्थी जो कम से कम घटाव का प्रश्न हल कर सकते थे, अखिल भारतीय स्तर पर वर्ष २०१८ में २८.२ प्रतिशत थे। वर्ष २०२२ में यह अनुपात घटकर २५.९ प्रतिशत हो गया, किन्तु वर्ष २०२४ में बढ़कर ३३.७ प्रतिशत हो गया। सरकारी विद्यालयों में कक्षा ३ के लिए यही अनुपात क्रमशः २०.९ प्रतिशत, २०.२ प्रतिशत और २७.६ प्रतिशत रहा। कक्षा ५ के विद्यार्थियों में साधारण भाग का प्रश्न हल करने की क्षमता वर्ष २०१८ के २७.९ प्रतिशत से घटकर वर्ष २०२२ में २५.६ प्रतिशत हुई और वर्ष २०२४ में बढ़कर ३०.७ प्रतिशत हो गई। इन परिणामों से यह स्पष्ट है कि सुधार की दिशा मजबूत है, परन्तु उपलब्धि का स्तर अभी भी सीमित है। यदि कक्षा ५ में भी लगभग सात में से पाँच विद्यार्थी भाग का प्रश्न हल नहीं कर पाते, तो आगे प्रतिशत, भिन्न, अनुपात, बीजगणित और उच्चतर गणित से संबंधित विषयों में कठिनाई होना स्वाभाविक है। इसलिए प्रारम्भिक गणित शिक्षण में केवल प्रक्रिया याद कराने के बजाय संख्या-बोध, दृश्य सामग्री, जीवन से जुड़े उदाहरण, मौखिक गणना और समस्या समाधान को अधिक महत्व देना आवश्यक है।

१०. उच्चतर कक्षाओं में अधिगम की चुनौती

प्रारम्भिक पढ़ने और गणना में सुधार उत्साहजनक है, किन्तु उच्चतर कक्षाओं के परिणाम यह स्पष्ट करते हैं कि विद्यालयी शिक्षा की चुनौती केवल बुनियादी कौशल तक सीमित नहीं है। परख राष्ट्रीय सर्वेक्षण २०२४ में कक्षा ६ के विद्यार्थियों का भाषा में राष्ट्रीय औसत लगभग ५७ प्रतिशत था, जबकि गणित में यह लगभग ४६ प्रतिशत और आसपास के संसार से संबंधित विषय में लगभग ४९ प्रतिशत रहा। कक्षा ९ में भाषा का औसत लगभग ५४ प्रतिशत, गणित का ३७ प्रतिशत, विज्ञान का ४० प्रतिशत और सामाजिक विज्ञान का ४० प्रतिशत रहा। यह अंतर विशेष रूप से गणित और विज्ञान के क्षेत्र में गंभीर है क्योंकि उच्चतर कक्षाओं में विषय-वस्तु अधिक अमूर्त, अवधारणात्मक और परस्पर संबंधित हो जाती है। यदि विद्यार्थी प्रारम्भिक वर्षों में बुनियादी अवधारणाओं को मजबूत रूप से नहीं समझता, तो आगे की कक्षा में नए विषय पुरानी कमजोरी पर निर्मित होते जाते हैं। इससे पाठ्यक्रम और विद्यार्थी की वास्तविक क्षमता के बीच दूरी बढ़ती है। विद्यालय सामान्यतः कक्षा के अनुसार पाठ्यक्रम आगे बढ़ाता है, जबकि एक ही कक्षा में विद्यार्थियों की वास्तविक अधिगम स्थिति बहुत भिन्न हो सकती है। परिणामस्वरूप शिक्षक के सामने चुनौती होती है कि वह पाठ्यक्रम भी पूरा करे और पिछली कक्षाओं की कमियों को भी दूर करे। उच्चतर कक्षाओं में अधिगम सुधार के लिए इसलिए आधारभूत पुनर्बलन, स्तरानुकूल सहयोग, अवधारणा-आधारित शिक्षण और नियमित निदानात्मक मूल्यांकन की आवश्यकता है।

११. लिंग, ग्रामीण-नगरीय और सामाजिक समूहों के आधार पर अंतर

राष्ट्रीय आँकड़े यह दर्शाते हैं कि प्रारम्भिक कक्षाओं में लिंग के आधार पर अधिगम अंतर अनेक पारंपरिक धारणाओं से कम है। परख राष्ट्रीय सर्वेक्षण २०२४ में कक्षा ३ की भाषा में छात्राओं का औसत लगभग ६५ प्रतिशत और छात्रों का लगभग ६३ प्रतिशत था, जबकि गणित में दोनों का प्रदर्शन लगभग ६० प्रतिशत था। इससे स्पष्ट होता है कि प्रारम्भिक गणितीय क्षमता को लिंग से जोड़कर देखने का कोई ठोस आधार नहीं है और उपयुक्त अवसर मिलने पर छात्राएँ समान या बेहतर प्रदर्शन कर सकती हैं। इसी प्रकार ग्रामीण और नगरीय विद्यार्थियों के बीच भी कक्षा ३ के स्तर पर अंतर बहुत छोटा रहा; ग्रामीण विद्यार्थियों का भाषा में औसत लगभग ६४ प्रतिशत और गणित में ६० प्रतिशत था, जबकि नगरीय विद्यार्थियों का औसत क्रमशः लगभग ६३ और ५९ प्रतिशत था। यह परिणाम संकेत करता है कि भौगोलिक स्थिति अपने आप में अधिगम का निर्णायक कारक नहीं है। सामाजिक समूहों के आधार पर कुछ अंतर अवश्य दिखाई देते हैं। अनुसूचित जनजाति विद्यार्थियों का औसत कई संकेतकों पर अन्य समूहों की तुलना में कम रहा, जो दुर्गम भौगोलिक परिस्थितियों, विद्यालयी भाषा और मातृभाषा के अंतर, शिक्षक उपलब्धता, सामाजिक-आर्थिक सीमाओं और संसाधनों की असमानता से संबंधित हो सकता है। इन परिणामों से यह निष्कर्ष निकलता है कि समान पाठ्यक्रम और समान परीक्षा पर्याप्त नहीं हैं; न्यायसंगत अधिगम के लिए अलग-अलग सामाजिक और भाषायी संदर्भों को ध्यान में रखते हुए समर्थन की आवश्यकता है।

१२. विद्यालय प्रबंधन और अधिगम का संबंध

विद्यालय के सरकारी, निजी या सहायता प्राप्त होने को अक्सर गुणवत्ता का सीधा संकेतक मान लिया जाता है, परन्तु नवीन राष्ट्रीय परिणाम इस धारणा को सरल रूप में स्वीकार नहीं करते। परख राष्ट्रीय सर्वेक्षण २०२४ में कक्षा ३ के स्तर पर राज्य सरकार के विद्यालयों के विद्यार्थियों का भाषा में औसत लगभग ६४ प्रतिशत और गणित में लगभग ६१ प्रतिशत था। निजी विद्यालयों में यह औसत क्रमशः लगभग ६४ और ६० प्रतिशत रहा, जबकि सरकारी सहायता प्राप्त विद्यालयों में भाषा और गणित का औसत थोड़ा कम था। ग्रामीण भारत के समयगत परिणामों में भी वर्ष २०२२ से २०२४ के बीच अनेक आधारभूत अधिगम संकेतकों पर सरकारी विद्यालयों के विद्यार्थियों में उल्लेखनीय सुधार दिखाई दिया। इससे यह स्पष्ट होता है कि विद्यालय प्रबंधन की श्रेणी अकेले अधिगम की गुणवत्ता निर्धारित नहीं करती। एक सरकारी विद्यालय मजबूत नेतृत्व, नियमित शिक्षक उपस्थिति, सक्रिय कक्षा-पद्धति और समुदाय के सहयोग से उत्कृष्ट परिणाम दे सकता है, जबकि अधिक संसाधन होने के बावजूद यदि शिक्षण प्रक्रिया कमजोर है तो अपेक्षित अधिगम नहीं होगा। इसलिए गुणवत्ता सुधार की चर्चा को केवल सरकारी बनाम निजी तुलना तक सीमित रखना विश्लेषण को संकुचित करता है। अधिक उपयोगी दृष्टिकोण यह है कि विद्यालय-स्तर पर शिक्षक सहयोग, नेतृत्व, कक्षा समय का उपयोग, नियमित मूल्यांकन, विद्यार्थियों की उपस्थिति, भाषा और परिवार का सहयोग जैसे कारकों को देखा जाए।

१३. आधारभूत संरचना, डिजिटल पहुँच और सीखने का वातावरण

विद्यालयी आधारभूत संरचना अधिगम का प्रत्यक्ष विकल्प नहीं है, फिर भी सुरक्षित, कार्यशील और संसाधनयुक्त वातावरण सीखने के लिए आवश्यक परिस्थिति निर्मित करता है। वर्ष २०२४-२५ के विद्यालयी प्रशासनिक आँकड़ों में देश के लगभग १४.७१ लाख विद्यालयों में से लगभग ९.५२ लाख विद्यालयों में संगणक सुविधा और लगभग ९.३४ लाख विद्यालयों में अंतरजाल सुविधा दर्ज की गई। लगभग १४.६१ लाख विद्यालयों में पेयजल उपलब्ध था, परन्तु विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए अनुकूल शौचालय की उपलब्धता अभी सार्वभौमिक नहीं थी। इन सूचकों से दो बातें स्पष्ट होती हैं। पहली, विद्यालयों में भौतिक और तकनीकी संसाधनों का विस्तार हुआ है; दूसरी, उपलब्धता की समानता और उपयोग की गुणवत्ता अभी भी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। किसी विद्यालय में संगणक उपलब्ध होना और उसका नियमित शैक्षिक उपयोग होना अलग बातें हैं। यदि उपकरण बंद पड़े हैं, शिक्षक को उनका उपयोग नहीं आता या विद्यार्थियों को पर्याप्त समय नहीं मिलता, तो संसाधन का अधिगम पर

प्रभाव सीमित रहेगा। इसी प्रकार पुस्तकालय की उपस्थिति तभी प्रभावी है जब पुस्तकों तक विद्यार्थियों की पहुँच हो और पढ़ने की संस्कृति विकसित की जाए। इसलिए अधिगम सुधार में आधारभूत सुविधाओं की गणना के साथ उनके उपयोग, रखरखाव और शैक्षिक एकीकरण पर भी ध्यान देना आवश्यक है।

१४. शिक्षक की भूमिका और कक्षा-अधिगम

विद्यालय के भीतर विद्यार्थी के अधिगम को प्रभावित करने वाले कारकों में शिक्षक की भूमिका केंद्रीय है। शिक्षक केवल पाठ प्रस्तुत नहीं करता, बल्कि वह विद्यार्थियों की पूर्व समझ को पहचानता है, कठिनाई का निदान करता है, उदाहरण चुनता है, प्रश्न पूछता है, अभ्यास करवाता है, प्रतिपुष्टि देता है और कक्षा में ऐसा वातावरण बनाता है जहाँ विद्यार्थी बिना भय के सीख सकें। यदि शिक्षक को अत्यधिक गैर-शैक्षणिक दायित्व, प्रशासनिक अभिलेख, सर्वेक्षण, विविध रिपोर्टिंग और अन्य कार्यों में व्यस्त रहना पड़े, तो वास्तविक कक्षा शिक्षण के लिए उपलब्ध समय और ऊर्जा कम हो सकती है। साथ ही शिक्षक प्रशिक्षण की गुणवत्ता भी महत्वपूर्ण है। केवल सामान्य व्याख्यान आधारित प्रशिक्षण के बजाय वास्तविक कक्षा समस्याओं, विद्यार्थी की कॉपियों, स्तरानुकूल गतिविधियों और विषय-विशेष कठिनाइयों पर केन्द्रित सहायता अधिक प्रभावी हो सकती है। शिक्षक को यह जानने की आवश्यकता होती है कि उसकी कक्षा में कौन-सा बच्चा किस स्तर पर है और उसे आगे बढ़ाने के लिए कौन-सी गतिविधि उपयुक्त होगी। इस दृष्टि से सतत आकलन का उद्देश्य अंक देना नहीं, बल्कि शिक्षण की अगली दिशा तय करना होना चाहिए। यदि मूल्यांकन केवल परीक्षा के अंत में किया जाता है तो कठिनाई बहुत देर से सामने आती है; यदि छोटे और नियमित मूल्यांकन होते हैं तो शिक्षक समय रहते सहायता दे सकता है।

१५. भाषा और बहुभाषिकता की चुनौती

भारत की भाषायी विविधता विद्यालयी अधिगम की शक्ति भी है और चुनौती भी। अनेक बच्चे घर में जिस भाषा या बोली का प्रयोग करते हैं, विद्यालय में आरम्भिक शिक्षा किसी दूसरी भाषा में प्राप्त करते हैं। जब बालक की परिचित भाषा और विद्यालयी भाषा के बीच बहुत अधिक अंतर होता है, तो वह शिक्षक के निर्देश, पाठ्यपुस्तक और प्रश्नों को समझने में अतिरिक्त कठिनाई अनुभव कर सकता है। प्रारम्भिक वर्षों में यदि शिक्षा बच्चे की परिचित भाषा से पूरी तरह अलग हो तो पढ़ने की प्रक्रिया केवल अक्षर पहचान तक सीमित हो सकती है और अर्थबोध कमजोर रह सकता है। भाषा की समस्या का प्रभाव अन्य विषयों पर भी पड़ता है क्योंकि गणितीय प्रश्न, पर्यावरण अध्ययन और विज्ञान की अवधारणाएँ भी भाषा के माध्यम से ही समझी जाती हैं। इसलिए बहुभाषी कक्षाओं में शिक्षक को स्थानीय शब्दावली, मौखिक व्याख्या, चित्र, गतिविधि और क्रमिक भाषा संक्रमण का उपयोग करना चाहिए। मातृभाषा या परिचित भाषा को शिक्षा से जोड़ना केवल सांस्कृतिक संरक्षण का प्रश्न नहीं, बल्कि समझ और अधिगम का प्रश्न भी है। विद्यार्थियों को विद्यालयी भाषा में दक्ष बनाने के साथ उनकी घरेलू भाषा को एक संसाधन के रूप में उपयोग करना अधिक समावेशी और प्रभावी दृष्टिकोण हो सकता है।

१६. माध्यमिक स्तर पर निरंतरता और अधिगम

विद्यालयी शिक्षा में माध्यमिक स्तर वह चरण है जहाँ विषय-वस्तु अधिक कठिन होती है, परीक्षा का दबाव बढ़ता है और परिवार तथा समाज की आर्थिक तथा सामाजिक अपेक्षाएँ भी विद्यार्थी पर अधिक प्रभाव डालती हैं। वर्ष २०२४-२५ में माध्यमिक स्तर की विद्यालय त्याग दर प्राथमिक स्तर की तुलना में काफी अधिक दर्ज की गई। यह अंतर केवल पहुँच की समस्या नहीं दर्शाता, बल्कि यह भी संकेत देता है कि कमजोर अधिगम विद्यार्थी के विद्यालय में बने रहने को प्रभावित कर सकता है। जो विद्यार्थी कई वर्षों से पाठ्यक्रम समझने में कठिनाई अनुभव कर रहा हो, वह उच्च कक्षा में स्वयं को लगातार असफल मान सकता है और विद्यालय से उसका मनोवैज्ञानिक संबंध कमजोर हो सकता है। आर्थिक दबाव, घर से विद्यालय की दूरी, परिवहन, घरेलू जिम्मेदारियाँ, बालिकाओं की सुरक्षा, परीक्षा का भय और रोजगार से जुड़ी अपेक्षाएँ इस समस्या को और जटिल

बनाती हैं। इसलिए माध्यमिक स्तर पर विद्यालय त्याग को केवल नामांकन से संबंधित प्रशासनिक समस्या मानना पर्याप्त नहीं है। विद्यालयों को कमजोर अधिगम वाले विद्यार्थियों की समय रहते पहचान, शैक्षणिक सहायता, परामर्श, लचीले पुनर्बलन कार्यक्रम और परिवार से संवाद की व्यवस्था करनी चाहिए।

१७. प्रमुख निष्कर्ष

अध्ययन के समेकित विश्लेषण से कुछ स्पष्ट निष्कर्ष सामने आते हैं। प्रथम, भारत में प्रारम्भिक अधिगम की दिशा वर्ष २०२२ के बाद सुधार की ओर गई है, विशेष रूप से पढ़ने और अंकगणित में। वर्ष २०२४ के परिणाम अनेक संकेतकों पर महामारी-पूर्व स्तर तक लौटे या उससे आगे बढ़े हैं। द्वितीय, सरकारी विद्यालयों में सुधार विशेष रूप से उल्लेखनीय है, जिससे यह धारणा कमजोर होती है कि सुधार केवल निजी विद्यालयों तक सीमित है। तृतीय, प्रारम्भिक अधिगम में प्रगति के बावजूद उच्चतर कक्षाओं में गणित, विज्ञान और अवधारणात्मक समझ की चुनौती गंभीर बनी हुई है। चतुर्थ, लिंग और ग्रामीण-नगरीय स्थिति के आधार पर प्रारम्भिक स्तर पर अंतर अपेक्षाकृत छोटा है, जबकि सामाजिक और भाषायी संदर्भ के आधार पर असमानताएँ अधिक महत्वपूर्ण हो सकती हैं। पंचम, विद्यालय की भौतिक सुविधाओं का विस्तार हुआ है, लेकिन उनकी उपस्थिति और वास्तविक शैक्षिक उपयोग के बीच अंतर को समझना आवश्यक है। षष्ठ, अधिगम परिणामों को केवल विद्यार्थी की व्यक्तिगत क्षमता का परिणाम नहीं माना जा सकता; वे शिक्षक, विद्यालय, परिवार, भाषा, समुदाय, पाठ्यक्रम, सामाजिक स्थिति और प्रशासनिक सहायता के संयुक्त प्रभाव का परिणाम हैं।

१८. प्रमुख चुनौतियाँ

भारत में अधिगम सुधार के सामने सबसे बड़ी चुनौती यह है कि राष्ट्रीय स्तर पर दिखाई देने वाली प्रगति अभी सभी बच्चों तक समान रूप से नहीं पहुँची है। प्रारम्भिक कक्षाओं में बड़ी संख्या में विद्यार्थी अपनी कक्षा के अनुरूप पढ़ने और गणना की क्षमता तक नहीं पहुँचते, जिससे उनके आगे के अधिगम पर संचयी प्रभाव पड़ता है। दूसरी प्रमुख चुनौती उच्चतर कक्षाओं में गणित और विज्ञान की अपेक्षाकृत कमजोर उपलब्धि है, जो केवल अभ्यास की कमी नहीं बल्कि अवधारणात्मक समझ, विषय-भय, पूर्व ज्ञान की कमजोरी और शिक्षण पद्धति से भी जुड़ी हो सकती है। तीसरी चुनौती राज्यों और जिलों की व्यापक विविधता है; राष्ट्रीय औसत अनेक स्थानीय समस्याओं को छिपा सकता है। चौथी चुनौती विद्यालयी भाषा और घर की भाषा के बीच अंतर है, विशेष रूप से जनजातीय और बहुभाषी क्षेत्रों में। पाँचवीं चुनौती शिक्षक पर बढ़ते गैर-शैक्षणिक दायित्व और कक्षा में विविध स्तरों के विद्यार्थियों को एक साथ पढ़ाने की कठिनाई है। छठी चुनौती माध्यमिक स्तर पर विद्यालय त्याग की अपेक्षाकृत अधिक दर है। सातवीं चुनौती यह है कि आधारभूत सुविधाओं और डिजिटल संसाधनों का विस्तार होने के बावजूद उनका गुणवत्तापूर्ण शैक्षिक उपयोग समान नहीं है। इन सभी चुनौतियों का समाधान एक समान राष्ट्रीय कार्यक्रम से नहीं बल्कि साझा राष्ट्रीय लक्ष्य और स्थानीय रूप से अनुकूलित रणनीतियों के संयोजन से संभव होगा।

१९. सुधार के लिए सुझाव

भारत में अधिगम परिणामों में स्थायी सुधार के लिए सबसे पहले आधारभूत साक्षरता और संख्याज्ञान को प्राथमिक कक्षाओं की वास्तविक कक्षा-स्तरीय प्राथमिकता बनाना आवश्यक है। प्रत्येक विद्यार्थी की पढ़ने और गणना की स्थिति को नियमित रूप से समझा जाए और उसे उसके स्तर के अनुरूप अभ्यास दिया जाए। पाठ्यक्रम पूरा करने को गुणवत्ता का मुख्य संकेतक मानने के बजाय यह देखा जाए कि विद्यार्थी ने क्या समझा। स्तरानुकूल शिक्षण, छोटे समूह, सहपाठी सहयोग, स्थानीय सामग्री और बार-बार अभ्यास इस दिशा में उपयोगी हो सकते हैं। गणित शिक्षण में प्रक्रियाएँ याद कराने के स्थान पर संख्या-बोध, दृश्य सामग्री, दैनिक जीवन की समस्याओं, अनुमान, मानसिक गणना और तर्क पर बल दिया जाना चाहिए। उच्चतर कक्षाओं में भी कमजोर

आधार वाले विद्यार्थियों के लिए पुनर्बलन की व्यवस्था होनी चाहिए ताकि उन्हें यह मानकर आगे न बढ़ाया जाए कि पिछली कक्षा का पूरा ज्ञान स्वतः प्राप्त हो चुका है।

दूसरा, शिक्षक सहायता को मजबूत करना अत्यावश्यक है। प्रशिक्षण को एकबारगी कार्यक्रम के बजाय सतत शैक्षणिक सहयोग के रूप में विकसित किया जाए। शिक्षक को विद्यार्थियों की वास्तविक कठिनाइयों के उदाहरण, उत्तर-पुस्तिकाओं का विश्लेषण, पाठ योजना, प्रश्न निर्माण और स्तरानुकूल गतिविधियों पर व्यवहारिक मार्गदर्शन मिले। विद्यालय प्रमुख की भूमिका भी केवल प्रशासनिक नियंत्रण तक सीमित न हो; उसे शिक्षण नेतृत्व, कक्षा निरीक्षण, शिक्षक सहयोग और अधिगम आँकड़ों के उपयोग से जोड़ा जाए। तीसरा, मूल्यांकन का उद्देश्य दंड या रैंकिंग नहीं, बल्कि सीखने की कठिनाइयों की पहचान होना चाहिए। छोटे, सरल और नियमित आकलन शिक्षक को यह समझने में सहायता करते हैं कि आगे किस बच्चे को किस प्रकार का सहयोग देना है। चौथा, बहुभाषी क्षेत्रों में परिचित भाषा के उपयोग और विद्यालयी भाषा की क्रमिक ओर बढ़ने की रणनीति अपनाई जाए। पाँचवाँ, माध्यमिक स्तर पर कमजोर विद्यार्थियों के लिए परामर्श, पुनर्बलन कक्षाएँ और परिवार से संपर्क की व्यवस्था विकसित की जाए ताकि अधिगम कमजोरी विद्यालय त्याग में परिवर्तित न हो। छठा, डिजिटल और भौतिक संसाधनों के लिए केवल उपलब्धता नहीं बल्कि उपयोग का आकलन किया जाए। सातवाँ, जिला और विद्यालय स्तर पर अधिगम आँकड़ों का उपयोग लक्षित सहायता के लिए हो, न कि केवल औपचारिक रिपोर्टिंग के लिए। इस प्रकार नीति, शिक्षक, विद्यालय और समुदाय के बीच समन्वित प्रयास अधिगम सुधार को अधिक टिकाऊ बना सकते हैं।

२०. निष्कर्ष

भारत की विद्यालयी शिक्षा ने पहुँच और नामांकन के क्षेत्र में व्यापक विस्तार प्राप्त किया है और नवीनतम साक्ष्य यह भी दर्शाते हैं कि बड़े पैमाने पर अधिगम सुधार संभव है। वर्ष २०२२ से २०२४ के बीच पढ़ने और आधारभूत अंकगणित में हुई प्रगति, विशेष रूप से सरकारी विद्यालयों में, इस बात का प्रमाण है कि लक्षित प्रयास, नियमित विद्यालयी संपर्क और आधारभूत कौशल पर ध्यान सकारात्मक परिणाम दे सकते हैं। फिर भी इस प्रगति को अधिगम समस्या की समाप्ति नहीं माना जा सकता। बड़ी संख्या में विद्यार्थी अभी भी अपेक्षित बुनियादी क्षमताओं तक नहीं पहुँचते और उच्चतर कक्षाओं में गणित, विज्ञान तथा जटिल अवधारणाओं से संबंधित परिणाम अपेक्षाकृत कमजोर हैं। इससे स्पष्ट है कि भारत के लिए अगला शैक्षिक चरण केवल बच्चों को विद्यालय तक पहुँचाने का नहीं, बल्कि प्रत्येक बच्चे को वास्तविक रूप से सीखने में सक्षम बनाने का है। यह लक्ष्य तभी प्राप्त होगा जब शिक्षण विद्यार्थी की वर्तमान क्षमता से प्रारम्भ हो, शिक्षक को पर्याप्त शैक्षणिक सहयोग मिले, मूल्यांकन का उपयोग सुधार के लिए किया जाए, भाषा और सामाजिक विविधता का सम्मान किया जाए तथा कमजोर अधिगम को समय रहते पहचाना जाए। विद्यालय की सफलता इस आधार पर मापी जानी चाहिए कि वहाँ से निकलने वाला विद्यार्थी पढ़ सकता है, समझ सकता है, गणना कर सकता है, तर्क कर सकता है और ज्ञान का उपयोग जीवन की समस्याओं में कर सकता है। यही दृष्टिकोण शिक्षा को मात्र उपस्थिति से वास्तविक क्षमता, और नामांकन से सार्थक अधिगम की दिशा में ले जाएगा।

संदर्भ

असर केन्द्र। (२०२५)। वार्षिक शिक्षा स्थिति प्रतिवेदन २०२४। प्रथम शिक्षा फाउंडेशन।

शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार। (२०२२)। राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वेक्षण २०२१: राष्ट्रीय प्रतिवेदन। विद्यालय शिक्षा एवं साक्षरता विभाग।

शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार। (२०२१)। निपुण भारत: समझ के साथ पढ़ने और संख्याज्ञान में प्रवीणता के लिए राष्ट्रीय पहल। विद्यालय शिक्षा एवं साक्षरता विभाग।

शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार। (२०२२)। आधारभूत अधिगम अध्ययन। विद्यालय शिक्षा एवं साक्षरता विभाग।

राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद। (२०२५)। परख राष्ट्रीय सर्वेक्षण २०२४: राष्ट्रीय प्रतिवेदन।

शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार। (२०२५)। विद्यालयी शिक्षा के लिए एकीकृत जिला सूचना प्रणाली २०२४-२५: राष्ट्रीय प्रतिवेदन। विद्यालय शिक्षा एवं साक्षरता विभाग।

शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार। (२०२५)। विद्यालयी आधारभूत सुविधाओं और नामांकन से संबंधित राष्ट्रीय सांख्यिकीय विवरण २०२४-२५। विद्यालय शिक्षा एवं साक्षरता विभाग।